



मोदी अपने मंत्रिमण्डल में फेरबदल शीघ्र ही करेंगे?

“द्रीम टीम” बनाने का प्रयास है, कुछ महत्वपूर्ण राज्यों
में होने वाले विधान सभा चुनावों के पहले

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-
नई दिल्ली, 30 मई जैसे-जैसे राज्यीय राजनीती में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नें भी मोदी के मंत्रिमण्डल के फेरबदल को लेकर अटके लें जैसे ही गई है। सत्ता के गलियारों से जुड़े सूतों का कहाना है कि देश जल्द ही एक “द्रीम टीम” को देख सकता है, जिसमें कुछ नए चेहरे केंद्रीय मंत्रिमण्डल में प्रमुख भूमिकाएं निभा सकती हैं।

इन घटनाक्रमों के बीच, राजनीतिक गलियारों में वह चर्चा जैसे पर है कि केंल से कांग्रेस के चारों सांसद शशि थरूर को विदेश मंत्री जैसे हाई-प्रोफल पट के पेशकश की जा सकती है। यह नामांकन कथित तौर पर टेबल पर शुरू हो गया है, हालांकि इसका विवरण सामान्य नहीं आया है। लेकिन इन अटकों ने पहले से ही आंतरिक संरचना और नीति-संबंधी पहचान के संकट से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में हलचल मचा दी है।

- चर्चाओं के अनुसार, अपनी पार्टी में अनदेखी से क्षुब्ध कई कांग्रेस के नेताओं को भी मोदी अपनी टीम में लेना चाहते हैं।
- “द्रीम टीम” में शशि थरूर को भी विदेश मंत्री का पद ऑफर हो सकता है। कांग्रेस में काफी बेचैनी है, इस “ऑफर” की संभावना से।
- सलमान खुर्शीद व मनीष तिवारी भी उन नेताओं के नामों की सूची में काफी ऊपर हैं, जो पार्टी के मत से शिव अपना मत रखते हैं। क्या मोदी इन नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से करीब-करीब भाजपा की नीति का समर्थन व्यक्त करने, का भी राजनीति लाभ उठायेंगे।
- उदाहरण के लिए, मनीष तिवारी का नाम कांग्रेस ने अपनी सूची में नहीं रखा था, पर, मोदी ने उन्हें भी भारत के “ऑपरेशन सिंदूर” को समझाने के लिए, विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया है, और, चर्चाओं के अनुसार, मनीष तिवारी ने ऑफर स्वीकार करने के बारे में अपनी स्वीकृति भी दे दी है।
- सलमान खुर्शीद ने भी हाल ही में इंडोनेशिया यात्रा के दौरान आर्टिकल 370 को रद्द करने के निर्णय को सही बताया, तथा कश्मीर के विधान सभा चुनाव में 65 प्रतिशत वोट पड़ने को साराहनीय बात बतायी। उनकी इस टिप्पणियों से भी कांग्रेस क्षुब्ध है, तथा भाजपा प्रसन्न।

थरूर द्वारा हाल ही में विवादाप्त संपर्क अधियान है और जिसे कांग्रेस नेता विहार चुनावों से पहले आजपा को समर्थन किया, जो कि एक सांस्कृतिक संप्रदायिक वोट-बैंक रणनीति के

समरावता उपद्रव प्रकरण में नरेश मीणा को जमानत नहीं

जयपुर, 30 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उच्चानव के दौरान एसटीमन भारत के बाद समरावता में हुए उदाहरण प्रकरण में आरोपी नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जिसके प्रवार

- देवली-उनियारा विधानसभा उपचानव के दौरान व बाद में हुए उपद्रव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर कई मामले दर्ज हुए थे। तथापि, एस. डी. एम. को थप्पड़ मारने के मामले में मीणा को राहत मिली है।

भटनागर की एकलायी ने यह आदेश नरेश मीणा की द्वितीय जमानत वाचिका को खारिज करते हुए दिए दूसरी और प्रतिस अनिल उपमन ने थप्पड़ कांड में मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिया है।

जिसके प्रवार भटनागर ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विधान आदेश दिया गया है। उक्त चतुर्वाह दिखाई है। खासकर अधिक, सर्वदलीय टीम का हिस्सा बनकर प्राक्षितन की तीव्र आलोचना करके सबको नज़रों के आदेश दिया है।

सरकार द्वारा अपने सांसदों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने के बाद विषयकी दलों ने इस मुद्दे को तूल

कांग्रेस ने शशि थरूर के नाम पर अपनी मोहर न लगाकर गलती करी?

शशि थरूर के भारत के ऑपरेशन “सिंदूर” के बारे में वाशिंगटन में दिए गए प्रस्तुतिकरण को काफी प्रभावशाली माना गया। पर, कांग्रेस को उसका “क्रैडिट” नहीं मिला।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-
नई दिल्ली, 30 मई। केंल से कांग्रेस संसदीय शिव प्रधान को, अमेरिका और अन्य देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाए जाने के बूढ़े पर कांग्रेस खुद असमंजस में फंस गई है।

- अभिषेक बनर्जी की यह “टिप्पणी” कि, “आतंकवाद पागल कृता है, तो पाकिस्तान उसकी जननी है, अतः, जननी को मारना ज्यादा ज़रूरी है, नहीं तो, नये पागल कृतों को जन्म देकर जननी हैं भारत भेजती ही रहेगी”, बहुत उल्लेखनीय व चार्चित रही।
- अभिषेक बनर्जी, अपनी इस संदर्भ में हुई जापान यात्रा के दौरान रास बिहारी बोस के स्मारक पर भी गये, और स्मारक की दूधी फूटी हालत की ओर भारत के राजदूत का ध्यान आकर्षित किया और जापान सरकार की निगाह में भी लाने का आग्रह किया।

विशेष करने से कांग्रेस की स्थिति बड़ी नहीं दिया। उपर, ममता बनर्जी ने जब सरकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हम पहलगाम की घटना के पहले की स्थिति में लगभग आ गये हैं’

पाकिस्तान के वरिष्ठतम सेना अधिकारी, जो पकिस्तान के, चेयरमैन ऑफ जॉइन्ट चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी “रॉयटर” को दिये गये इन्टरव्यू में यह दावा दिया

-डॉ. सतीश मिश्रा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-
नई दिल्ली, 30 मई। इस्तमाबाद ने दावा किया है कि दोनों ही पक्ष अपनी सीमा पर सेना के जमानडे को कम करके उसी स्तर पर ले जाने के बढ़ावोंके हैं, जिस पर इस माह दोनों पेंडेसियों के बीच संघर्ष से अपेक्षित रहा है। लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर खालोश बने रहना बेहतर समझा है।

जनरल साहिं शर्माद मिश्रा, जो पाकिस्तान जॉइन्ट चीफ स्टाफ के चेयरमैन है, और क्या किया जाएगा तो कमान आपको जानना चाहता है। उसके बाद यह अपनी सेनाओं को अपेक्षित करना चाहता है।

दोनों पक्षों ने पिछले दशकों की सबसे प्रचंड लड़ाई के उन चार दिनों में फाइटर जैट, मिसाइल, ड्रोन आदि

- जॉइन्ट चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने इन्टरव्यू में यह भी कहा कि, 22 अप्रैल की स्थिति तक पहुंच ही गये हैं, और धीरे-धीरे दोनों सेनाएं अपने जवानों का पीछे हातने का कार्यक्रम जारी करते हुए हैं और हम शीघ्र ही 22 अप्रैल के पहले की स्थिति में शीघ्र पहुंच जायेंगे।
- भारत ने जनरल शाहिर रायशाद मिर्जा के दावे को अभी चैलेंज नहीं किया और न ही प्रतिक्रिया व्यक्त की।

आर्टिकों को काम में लिया था और पाक-समर्थनीय “आतंकियों” को चार दिन बाद, युद्धावारम को जिम्मेवार रहाया था। इस्तमाबाद ने अपनी सीमा पर सेनाओं के अंशकालों की कार्य दिवस पीढ़ी ने याचिका को अपार्टमेंट के बाहर के दौरान आपोर के द्वारा देखा गया था।

परमाणु शक्ति संपन्न इन दोनों पर है और यह अपनी आप में हुए है।

उस दूसरे दिन, 22 अप्रैल को, भारत के इस आपोर के खंडन के बाहर के दौरान आपोर के द्वारा देखा गया था।

साथ मई को, भारत ने सीमा पर शुरूआत 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए के “आतंकियों के तिकानों” पर उस आतंकी हमले से हुई, जिसमें 26 मिसालें दागी थीं तथा पाकिस्तान ने आपोर के द्वारा बाती संस्था नेशनल दुश्मनों के बीच हुई इस लड़ाई की ओर नीति थी।

दोनों देशों ने बोर्ड ऑफ एजेंसिनेशन (एनबीई) यह दोनों देशों ने देखा है। नई दिल्ली ने इस घटना के लिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नीट पीजी परीक्षा एक ही पाली में कराएं’

नई दिल्ली, 30 मई। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल के स्नातकोत्तर पाद्यक्रमों में दायिले के लिए 15 जून से होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2025 वो की जावायी है। अपनी नीतीयों को जमानत करने का शुरुकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल बोर्ड ऑफ एजामिनेशन को यह निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इसके लिए आवश्यक प्रबंध देतु वे परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का आवेदन कर सकते हैं।

न्यायालयीय विक्रम नाथ, न्यायालयी संघर्ष कुमार और न्यायालयीत एन वी अंगारेका की अंशकालों की कार्य दिवस पीढ़ी ने याचिकाकारी अदिति और अन्य की याचिका पर संघर्षित पक्षों की दलील सुनने के बाद इस नीती पीजी को आपोर के द्वारा देखा गया था।